resources allocated for one district will be diverted to the other district; and that the State Government will release the allocated funds within a time-bound programme, rather than procrastinating on it and seeing that the amount remains unspent and has been put in a bank to earn some interest?

SHRI MURASOLI MARAN: Sir, the in-built protections are there in the guidelines.

MR. CHAIRMAN: Question No. 263.

Assignment of fertiliser project to M|s. Snam Progetti

*263. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that M|s. Snam Progetti of Italy was assigned under a deal to set up units of Phulpur Fertiliser Project in Uttar Pradesh;

(b) whether it was also assigned fertiliser contract at Trombay during 1974-75;

(c) whether it is also a fact that M|s Gujarat Narmada Valley Fertiliser Company (GNFC) was asked to cancel its contract with M|s. Toyo of Japan and then it was assigned to M|s. Snam Progetti of Italy;

(d) if so, what are the details of the total assignments of M|s. Snam Progetti in the country under the project with the Ministry; and

(e) the name and the locations of each project alongwith the progress made so far in each case?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI DEVI LAL): (a) Yes, sir M/s. Snam Progetti were given the contract for engineering consultancy of the urea plant of Phulpur based on international competitive bidding.

(b) Yes, Sir for Ammonia and Urea plants of Trombay-V in December 1976.

(c) M|s. Gujarat State Fertiliser Company as the promoters of M|s. Gujarat Narmada Valley Fertiliser Company entered into a contract with M/s. Snam Progetti for the urea plant in Sept., 1976. Since a contract had not been signed with M/s. Toyo Engg. Corporation of Japan the question of its cancellation did not arise.

(d) and (e) The details of scope of work assigned to M|s Snam Progetti, the fees paid|payable as per contract and the status of the projects are given in the statement attached. [See Appendix CLIII. Annexure No. 88].

डा. बापू कालदाते : सभापति, जी, यह सारे प्रश्नों का विस्तारित उत्तर यहां प्राप्त हुआ, यह हमें अच्छी बात लगी । यह स्नेम प्रोगेत्ति और इस एसोसियेट के बारे में देश में काफी चर्चा चलती रही । अगर इसमें यह जुड़ा हुआ निवेदन पढेंगे तो इसका भी पता लगेगा कि देश में जितने –जितने फर्टिलाइजर्स के यूनिट है, इसमें इसी कंपनी को सहभाग सबसे ज्यादा गया है । यह ठीक है कि उन्होंने यह कहा है कि गुजरात जी० एन०एफ०सी० वाला कांट्रेक्ट नहीं दिया था, लेकिन क्या यह बात सही है कि जापान की टोयो कंपनी को लैटर आफ इण्टेण्ट भेजा गया था ? अगर यह लेटर आफ इण्टेण्ट भेजने के बाद दूसरे को कांट्रेक्ट दिया गया तो ऐसा क्यों हुआ ? यह मेरा पहला "अ" सवाल है। दूसरा "ब" सवाल यह है कि सरकार आज आत्मनिर्भरता की बात कर रही है, उसको ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तान में जो कंसलटेन्सी एजेन्सी मौजूद है, उपलब्ध है, जो कई सालों से काम करती है, जैसे पी०डी०आई० एल०, एफ० जी० ओ० या फेक्ट है, इनको बढावा देकर बाहर की कंपनीयों के साथ रिश्ते कम करें और हम ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर होने की दिशा में प्रयास करें। इस दृष्टि से क्या सरकार फिर से इस बारे में सोचकर भारतीय कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठा रही है ?

श्री देवी लाल : चैयरमैन साहब, मेज पर सारे सवालों के जवाब रखने के बाद यह बात जाहिर होती है कि इस कंपनी को बहुत सी जगह पिछले सालों में ठेके दिए गए हैं । इस चीज को सामने रखते हुए कि खाद की जरूरत कितनी है, सबसिडी किस ढंग से दी गई है और दूसरे कारखानों को क्यों नजरअंदाज किया गया, इसके लिये रिव्यू किया जा रहा है कि और जब रिव्यू हो जाएगा तो उसके बाद सारे हालात आपके सामने रख दिए जायेंगे ।

डा० बापू कालदाते : क्या यह सही है कि पिछली सरकार ने कोई निर्बन्ध हुए थे, जिसके कारण यहां के फर्टिलाइजर के जो भी यूनिट आते थे, उभरकर आते थे या नए बनने वाले थे, इसमें स्नेम प्रोगेत्ती के साथ ही वह बात करते रहे, इस ढंग के या कोई निर्बन्ध थे ? अगर है, तो यह सरकार उस पर क्या सोच रही है ? जहां तक सामग्री का सवाल है, इक्यूपमेंट का सवाल है, वहां तक सरकार यह इजाजत दे कि जिन कंपनियों से अच्छे इक्यूपमेंट मिले, जिन कंपनियों से बेहतर टेक्नोलोजी मिले उनके साथ व्यवहार कर सकते हैं । ऐसी इजाजत देने का कोई प्रस्ताव या कोई निर्णय सरकार ने किया है क्या ?

श्री देवी लाल : इन सभी बातों पर गौर किया जा रहा है क्योंकि जिस ढंग से इस कंपनी को काम दिया गया है, यह तो बहुत बहुत बड़ी प्रभु की माया है। . . (**व्यवधान**)

डा० बापू कालदाते क्या इसकी जांच की जाएगी ?

श्री देवी लाल : इसके लिए रिव्यू किया जा रहा है । सारे हालात की पड़ताल की जा रही है कि कारण क्या है । जब सारे कारण सामने आ जाएंगे तो आपके सामने रख दिए जाएंगे ।

MR. CHAIRMAN: Yes, Mr. Kulkarni.

SHRI A. G. KULKARNI: Sir, I would like to know one thing from the honourable Minister. As my colleague, Dr. Kaldate, has suggested, the awarding of the contracts to M/s. Snamprogetti has almost been done in a monopolistic fashion and it seems that eleven contracts have been given to them costing about Rs. 22,000 crores!

So I am really surprised as to what happened to Government's intentions, of both the previous Government as well as the present Government wanted to encourage self-reliance. But now it seems that self-reliance has been given a go-bye. I only quote for the information of the Deputy Prime Minister. . .

MR. CHAIRMAN: वह तो बापू कालदाते जी ने पूछ लिया है । He has already asked that question whether they will give it to the local consultants when they are there.

आप सवाल कीजिए ।

SHRI A. G. KULKARNI:

मैं लम्बा सवाल नहीं करूंगा ।

I am quoting a study of the Working Group on Fertilizers in the Eighth Plan. They have said: "The Government choice of Snam Progetti as the prime construction company for fertilizer project in the Seventh Plan went against national interest." In this connection the World Bank observation. . . .

MR. CHAIRMAN: What is the question?

SHRI A. G. KULARNI: My question is whether he has seen the World Bank Report's observation that in all these projects the country lost between Rs. 75 to Rs. 150 crores per project. Would the Deputy Prime Minister assure this House that instead of appointing committees and commissions which do not serve any purpose, he would take a decision in his own Ministry as to how to recover these amounts from this firm which has been gone as confirmed by the World Bank?

श्री देवी लाल : आनरेबल मैम्बर ने जो कहा है, यह सरकार के ध्यान में है । इन सभी बातों पर गौर किया जाएगा कि सारे ठेके इसी कंपनी को क्यों दिए हैं ?

मुल्क में खाद की जो जरूरत थी उसको क्यों नहीं सामने रखा गया ? ये सब बातें रिव्यू की जा रही हैं । उसका फैसला जब हो जाएगा उसके बाद आपके सामने सारे हालात रख दिए जाएंगे । जितनी परेशानी आपके दिमाग में चल रही है, उससे ज्यादा मेरे दिमाग में है ।

SHRI A. G. KULKARNI: Is this a reply?

MR. CHAIRMAN: He has agreed with you. वह आपकी बात मान गए ।

SHRI A. G. KULKARNI: I have great respect for Devi Lalji for his rural orientation...

MR. CHAIRMAN: He has respect for you, mutual respect.

SHRI A. G. KULKARNI: But he must know that the country has lost about Rs. 1200 crores. So will he place this information before the House in the next Session so that it will satisfy me and him also?

श्री सभापति : वह कह रहे हैं कि मालूम है उन्हें और वह देख रहे हैं ।

श्री देवी लाल : मैं यही बात आप लोगों को अर्ज कर रहा हूं । ऑनरेबल मैम्बर ने जो पूछा है, बिल्कुल बेजा पूछा है । सारे हालात देखकर, उसपर गौर किया जा रहा है और अगले सैशन में वह सारे हालात आपके सामने रख दिए जाएंगे ।

श्री विश्वजित पृथ्वीजित सिंह : अध्यक्ष महाराज,... (व्यवधान)

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: If the Prime Minister is a Raja, does it mean that the Chairman becomes a Maharaja?

SHRI VISHVJIT P. SINGH: Let me tell you very clearly, it is a mark of respect to say 'Adhyaksha Maharaj'. There is nothing wrong with it. I always say it when I speak in Hindi...

MR. CHAIRMAN: I am neither a Raja nor a Maharaja.

अरे भई मैं तो आपका साथी हूं ।

श्री विश्वजित पृथ्वीजित सिंह : अध्यक्ष महाराज, मैं उप प्रधान मंत्री से कुछ निवेदन करूंगा, उनसे पूछूंगा । पहली बात तो यह मैं उनसे जानना चाहता हूं कि यह जो कम्पनी है —स्नेम प्रोगेट्टी—इसके मालिक कौन हैं ? मुझे बताया गया है कि यह सरकारी कम्पनी है, यह कोई प्राइवेट कम्पनी नहीं है । यह सरकारी कम्पनी है, जिस देश की कम्पनी है उनका कोई पब्लिक सैक्टर है, उसकी कम्पनी है । दूसरा जो इन्होंने यह स्टेटमेंट दिया है उसमें उसका जो लास्ट कॉलम है, उसमें हर जगह पर यह लिखा हुआ है

"....started commercial production on: ...."

उसमें सब डेट्स दिए हुए हैं । महोदय, इसमें यह लगता है कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ज्यादातर ये सब कमप्लीट हो चुके हैं, मुकम्मल हो चुके हैं और इनसे कार्मशियल प्रोडक्शन शुरू हो चुका है । ये सब प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुल हैं ।

मैं माननीय उप-प्रधान मंत्री जी से पहली बात यह जानना चाहता हूं कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये सब टाइम पर बन गए थे ? अगर ये टाइम पर बन गए थे तो इनका जो कार्मशियल प्रोडक्शन है, वह जैसा आईडिया था कि ऐसा होगा, वैसा हुआ है ? अगर वैसा हुआ है तो इनको डिस-क्वालिफाई करने का निर्णय कैसे लिया गया, यह मुझे बताया जाए ।

श्री देवी लाल : मैं मेम्बर साहब को यह बता दूं कि कंपनी इटली की है इसलिए इसके लिए देखभाल की जा रही है । जैसे ही यह हो जाएगा, पता लग जाएगा आपके सामने रख दिया जाएगा ।

श्री विश्वजित पृथ्वीजित सिंह : देखिए बात यह है कि वे मेरे बुजुर्गवार हैं, मैं उनको बहुत आदर-सम्मान देता हूं और मैं उनको ताऊ भी कहता हूं । पर फिर भी मैं

यह कहना चाहता हूं कि जो मैंने सवाल किया था उसके दो भाग हैं—पहला यह कि यह पब्लिक सेक्टर की कंपनी है कि नहीं, उसका जवाब दीजिए और दूसरा यह कि जो-जो प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हुए, ये टाइम पर मुकम्मल हुए या नहीं और ठीक तरीके से मुकम्मल हुए या नहीं । अगरचे ये ठीक तरह से और टाइम पर मुकम्मल हुए तो इनका रिव्यू क्यों किया जा रहा है ?

श्री देवी लाल : मैं ऑनरेबल मेंबर को जवाब दे रहा हू कि पब्लिक सैक्टर कंपनी है इसलिए जो बार-बार यह घोटाला हुआ है, यह तो प्रभु की लीला है । मैं उसकी पड़ताल कर रहा हूं . . . मैं जब रिपोर्ट हाउस के सामने रखूगा तो आपको तसल्ली हो जाएगी । मैं अभी इसी काम में लगा हुआ हूं ।

श्री विश्वजित पृथ्वीजित सिंह : अध्यक्ष महाराज, मेरी मदद कीजिए । ऐसे नहीं लेगा ।

Doubling of railway tracks in Kerala

*264. SHRI E. BALANANDAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government are taking any steps to speed up the work of doubling the railway tracks in Kerala keeping in view the inadequate train facilities in Kerala; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

Yes, Sir. However, the train services in Kerala are considered adequate for the present level of passenger traffic.

In Kerala, the section between Palghat and Ernakulam is already doubled. Between Ernakulam and Kayankulam, an alternative B.G. line has been proposed for construction. Of this, Ernakulam-Alleppey (57 km) has already been commissioned on 15.10.1989. Work on Alleppey-Kayankulam (43 km) is in progress and when completed, it will provide two lines between Ernakulam Kayankulam. Doubling between Kayankulam and Quilon (41 km) was approved in the Budget for 1989-90 and between Quilon and Trivandrum Central (65km) has been included in the Budget for 1990-91. A survey for doubling of Shoranur-Mangalore (307 km) section has also been included in the Budget for 1990-91.

(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Mr. Balanandan, you don't want to ask a supplementary? (*Interruptions*) It is all right. Question No. 265. (*Interruptions*)

SHRI ARANGIL SREEDHARAN: Sir, I wanted to ask a supplementary on Question No. 264.. How can you go to the next. . .(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please take your seat.

SHRI ARANGIL SREEDHARAN: Sir,. . .

MR. CHAIRMAN: Please take your seat. (*Interruptions*) Please take your seat. I am hearing nobody now. I am going by Rules. These are the Rules. These are the Rules. These are the Rules. He did not want to put a supplementary. I can't force him.

Next question. Question No. 265.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में संचालन समिति की नियुक्ति

*265. श्री राम जेठमलानी :

सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :†

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक वितरण को वर्तमान

† सभा में यह प्रश्न सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा द्वारा पूछा गया ।